राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पेट.) संख्या 7477/2024

1. गोरधन लाल सोनी पुत्र रामनिवास सोनी, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी छोटीखाटू, बारला बाजार, जिला। नागौर, राज.
2. शोभा देवी पत्नी गोरधन लाल सोनी, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी छोटीखाटू, बारला बाजार, जिला। नागौर, राज.
3. ललिता सोनी पुत्री गोरधन लाल सोनी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी छोटीखाटू, बारला बाजार, जिला। नागौर, राज.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. कमला देवी पत्नी श्याम सुंदर सोनी, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी के.जी. कॉम्प्लेक्स और दुर्गा माता मंदिर के पीछे, रानी बाजार, पुलिस स्टेशन कोटगेट, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री चेतन प्रकाश सोनी। श्रीमती सरिता सोनी।
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पीपी।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय

[1]24/10/2024

1. यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने में अक्सर अपनाई जाने वाली भ्रामक

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

प्रथा को दर्शाता है, बीएनएसएस की धारा 175 (सीआरपीसी की धारा 156 के अनुरूप) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, यांत्रिक तरीके से और न्यायिक दिमाग के उचित उपयोग के बिना, भले ही कथित अपराधों के तत्व न भी साबित हुए हों। इस तरह का लापरवाह दृष्टिकोण, बदले में, आरोपी व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, जिससे उन्हें संदिग्ध के रूप में जमानत लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है - या तो अग्रिम या वैकल्पिक रूप से, नियमित - यदि उन्हें एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया है और, यदि आरोप पत्र पहले ही दायर किया गया है, तो एक विचाराधीन कैदी के रूप में, अदालतों में मुकदमे की उत्पीड़न, विनम्रता और पीड़ा का सामना करना पड़ता है।

[1]**11.12.2024** को सुधार के बाद अपलोड किया गया

2. याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 3 क्रमशः शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के दामाद, बेटी और पोती (याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 की बेटी होने के नाते) हैं। वे धारा 420/406/120 बी आईपीसी के तहत कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 266 दिनांक 27.09.2024, पीएस कोटगेट, बीकानेर को रद्द करने और परिणामी कार्यवाही की मांग करते हैं।

<u>तथ्य</u>

3. आरोपित एफआईआर के अनुवादित संस्करण के अनुसार तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है:-

> “आज दिनांक *27.09.2024* को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर से धारा *175 (3) (*बीएनएसएस*)* के अंतर्गत डाक के माध्यम से निम्नलिखित शिकायत प्राप्त हुई, जो शिकायतकर्ता श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्याम सुंदर जाति सोनी, उम्र *72* वर्ष, निवासी के.जी. कॉम्प्लेक्स, दुर्गा माता मंदिर के पीछे, पुलिस स्टेशन कोटगेट,

1

बीकानेर द्वारा आईपीसी की धारा 420, 406, 120 बी के अंतर्गत दर्ज कराई गई।

x-x-x-x-x-x-x-x

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, की अदालत में।

बीकानेर

कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्याम सुंदर जाति सोनी, उम्र 72 वर्ष, निवासी के.जी. कॉम्प्लेक्स, दुर्गा माता मंदिर के पीछे, बीकानेर।
शिकायतकर्ता
बनाम

1. गोरधन लाल सोनी, पुत्र रामनिवास सोनी, निवासी छोटी खाटू, बड़ला बाजार, जिला नागौर।
2. शोभा देवी पत्नी गोरधन लाल सोनी निवासी छोटी खाटू, बड़ला बाजार, जिला नागौर।
3. ललिता सोनी पुत्री गोरधन लाल सोनी निवासी छोटी खाटू, बड़ला बाजार, जिला नागौर।

आरोपी
शिकायत धारा 175 (3) बीएनएसएस
धारा 61, 316 (2), 318 (4) बीएनएस के अंतर्गत।
महोदय,

शिकायत निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है:-

1. मैं, परिवादी, कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्यामसुंदर जाति सोनी, उम्र 70 वर्ष, निवासी के.जी. कॉम्प्लेक्स के पीछे, दुर्गा माता मंदिर के पीछे, बीकानेर, एक विधवा हूँ। मेरे दो बेटे और चार बेटियाँ हैं।
2. मेरे एक बेटे भवानी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मेरी बेटी शोभा की शादी छोटी खाटू के गोरधन लाल सोनी से हुई जो मेरे सबसे बड़े दामाद हैं और परिवार ने शोभा और उसके पति पर भरोसा करें।
3. पूर्व में भी आरोपियों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी, जिससे पारिवारिक कलह हो गई थी। मेरे पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने मेरा विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए क्षमा मांगी। परन्तु उनके समझौते के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, अर्थात मेरी सम्पत्ति व धन (धन, सोना, चांदी) हड़पने की उनकी मंशा थी। धीरे-धीरे यह बात मेरे सामने स्पष्ट हो गई और मुझे इन दोनों का असली चेहरा पता चल गया।

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

4. कि मेरे पति व पुत्र भवानी की मृत्यु के पश्चात मैं अकेली रह गई थी। इसलिए मेरी पुत्री शोभा व उसका पति गोरधन लाल सोनी मुझसे मिलने आते थे। मेरे पति व पुत्र की मृत्यु के पश्चात मैं गहरे सदमे में थी, जिसके कारण मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी।

5. कि मेरे दामाद गोरधन लाल सोनी दिनांक *21.01.2021* को बीकानेर आए और मुझे फोन करके कहा कि उन्हें कैमरा खरीदना है और मैं *1* लाख रुपए लेकर केईएम रोड पर उनके पास आ जाऊं। मैं, परिवादी, एक लाख रुपए लेकर केईएम रोड पहुंचा और गोरधन जी के लिए कैमरे का भुगतान किया। गोरधन जी ने कैमरा अपने बेटे ललित को देकर खाटू भेज दिया।

6. दिनांक *21.05.2021* को गोरधन जी पुनः मेरे घर आए और मुझसे अपनी निजी जरूरत के लिए दो लाख रुपए मांगे। मैंने पुनः गोरधन जी को दो लाख रुपए दे दिए। वे उस रात मेरे घर रुके और दिनांक *22.05.2021* को सुबह दो लाख रुपए लेकर चले गए।

7. दिनांक *21.09.2021* को मेरी बेटी शोभा और दामाद गोरधन लाल सोनी अपने *5* वर्षीय पोते के साथ मेरे घर आए और दिनांक *22.09.2021* को यहीं रुके। दिनांक *23.09.2021* को गोरधन जी व शोभा ने अपनी निजी जरूरतों के लिए दो लाख रुपए मांगे, इस प्रकार उन्होंने मुझसे दो लाख रुपए, *100* ग्राम सोना व *2* किलो *700* ग्राम चांदी ले ली और चले गए।

8. दिनांक *26.10.2021* को गोरधन जी ने मुझे फोन करके खाटू आने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंक पासबुक व चेक बुक साथ लेकर आओ। अपने दामाद गोरधन जी के कहने पर मैं खाटू गया और खाटू पहुंचने पर गोरधन जी ने मुझसे चेक पर हस्ताक्षर करवाकर बैंक से *1,50,000* रुपए निकलवा लिए। पूरी राशि मेरे दामाद गोरधन लाल सोनी ने ले ली। दिनांक *28.03.2022* को मेरी बेटी शोभा व गोरधन लाल जी अपने दामाद व बेटी पूजा के साथ पुनः मेरे घर आए। रात भर वे रुके और *29.03.2022* को सुबह जाते समय उन्होंने दो लाख रुपए की मांग की। मैंने दो लाख रुपए अपने दामाद गोरधन जी को दे दिए। जाने से पहले उन्होंने मेरे सोने के धागे, सोने के लॉकेट-*2*, सोने की अंगूठी-*1*, *1* जोड़ी झुमके और एक जोड़ी चांदी की पायल, चांदी की तगड़ी, *2* चांदी की अंगूठी और एक जोड़ी बिछिया जो कुल *500* ग्राम चांदी थी, ले लिए।

9. इस तरह मेरे दामाद गोरधन लाल सोनी ने धोखे और धोखाधड़ी से मुझसे *8,50,000/-* रुपए *(*आठ लाख पैंतालीस हजार रुपए*)* और *100* ग्राम सोना, *2* किलो *700* ग्राम चांदी, सोने और चांदी के आभूषण ले लिए। जब मैंने उधार दिए गए पैसे और सोने-चांदी के आभूषण मांगे तो उन्होंने मना कर दिया और अब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करते हैं।

मेरी पुत्री शोभा भी अपने पति के साथ इस षडयंत्र में सम्मिलित है। मेरा पोता जो गोरधन जी सोनी का पुत्र है, भी इस षडयंत्र में बराबर का भागीदार है।

10. मैं परिवादी ने उपरोक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना कोटगेट बीकानेर में परिवाद प्रस्तुत किया है तथा दिनांक .. *(*दिनांक स्पष्ट नहीं*)* को पुलिस अधीक्षक बीकानेर को भी परिवाद प्रस्तुत किया है, परन्तु आज दिनांक तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

11. परिवादी संबंधित पुलिस अधीक्षक के क्षेत्राधिकार में आता है। परिवाद में परिवाद की सीमा एवं न्यायालय शुल्क संलग्न है। अतः परिवाद को धारा *175(3)* सीआरपीसी के तहत शपथ पत्र सहित प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आरोपीगणों के विरुद्ध धारा *61, 316(2), 318(4)* बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

*(*शिकायतकर्ता*)*
कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्यामसुंदर जाति सोनी
निवासी के.जी. कॉम्प्लेक्स के पीछे,
दुर्गा माता मंदिर के पीछे, बीकानेर।
*(*जोर दिया गया*)*

x-x-x-x-x-x-x-x

एफ.आई.आर. प्राप्त होने पर, उपरोक्त अपराध धारा *420, 406, 120* बी भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाता है और जांच श्री प्रवीण कुमार, हैड कांस्टेबल *138* को सौंपी जाती है। एफ.आई.आर. संख्या और समय सी.सी.टी.एन.एस. द्वारा दिया जाएगा लेकिन इसे नीचे अलग से उल्लेखित किया जाएगा। नियमानुसार जारी एफ.आई.आर. की एक प्रति शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जाएगी।

ए

सडी/
गौरव बोहरा
सब इंस्पेक्टर"

4. इस प्रकार एफआईआर दर्ज की गई। इसके पंजीकरण के बाद, मामले में जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य की अभियोजन मशीनरी जिम्मेदार है। इसके बाद शिकायतकर्ता की भूमिका अभियोजन राज्य मशीनरी की सहायता करने तक सीमित है। इस मामले में राज्य/अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विद्वान लोक

अभियोजक द्वारा किया गया है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता को नोटिस देना अनावश्यक लगता है और इसे समाप्त किया जाता है।

प्रस्तुतियाँ

5. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। शिकायतकर्ता बिना किसी विश्वसनीय सबूत के एक निराधार कहानी गढ़कर जांच एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। एफआईआर याचिकाकर्ताओं को परेशान करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक स्पष्ट प्रयास प्रतीत होता है।

6.1. याचिका में उल्लेखित बातों का हवाला देते हुए कि एफआईआर में कथित रूप से ऋण पर दी गई धनराशि, सोना और चांदी का उल्लेख किया गया है, यह तर्क दिया गया कि वास्तव में संपत्ति (प्लॉट नंबर 1) के हस्तांतरण के लिए 04.09.2020 के एक समझौते के तहत दिया गया था। 123, विशाल नगर, मेड़ता सिटी, नागौर) शिकायतकर्ता ने स्वयं ही तीसरे पक्ष श्री विजेंद्र कुमार को उच्च मूल्य पर संपत्ति बेचकर इस समझौते का उल्लंघन किया। अब वह अपने अनुबंध के उल्लंघन को छिपाने के लिए धोखाधड़ी का झूठा दावा कर रही है।

6.2. विद्वान वकील ने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ताओं के पास शिकायतकर्ता को कोई भी पैसा वापस करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं था, क्योंकि उक्त राशि एक संपत्ति लेनदेन का हिस्सा थी। शिकायतकर्ता ने गलत धारणा बनाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है कि याचिकाकर्ताओं पर उसका पैसा बकाया है।

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

6.3. विद्वान वकील ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता की कार्रवाई निहित स्वार्थों और संपत्ति लेनदेन के उसके पक्ष में न होने के बाद याचिकाकर्ताओं से बदला लेने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित है। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग कर रहा है।

6.4. इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में भी अस्पष्ट देरी हुई है, उन्होंने तर्क दिया। हालांकि शिकायतकर्ता का दावा है कि घटनाएं 2021 से शुरू होने वाली अवधि में हुईं, लेकिन एफआईआर केवल 27.09.2024 को दर्ज की गई। यह देरी आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि एफआईआर याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के लिए बाद में दर्ज की गई थी।

6.5. जो भी हो, विवाद पूरी तरह से दीवानी है और अनिवार्य रूप से संपत्ति के मुद्दों से जुड़ा एक पारिवारिक मामला है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि धोखाधड़ी, विश्वासघात और साजिश के आरोप सभी निराधार हैं।

7. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि इस स्तर पर इस न्यायालय की कोई सहूलियत वारंट नहीं है। जांच चल रही है। यदि किसी अपराध का कोई दोष नहीं पाया जाता है, तो कानून के अनुसार एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की जाएगी। इसके विपरीत, यदि पर्याप्त सामग्री का पता चलता है, तो अपराध के घटित होने पर आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। इसलिए, वह याचिका खारिज करने की मांग करता है।

लागू कानूनी प्रावधानों की चर्चा और विश्लेषण

8. और लागू कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एफआईआर की उत्पत्ति पर गौर करना भी उचित होगा। इसलिए, आइए हम एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली शिकायत पर विद्वान सीजेएम द्वारा पारित दिनांक 23.09.2024 के आदेश को देखें। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

द्वारा पारित दिनांक 23.09.2024 के उक्त आदेश (जो इन कार्यवाहियों में चुनौती के अधीन नहीं है) की अनुवादित प्रति सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई, जो इस प्रकार है:-

"उपस्थित : परिवादी कमला देवी
अपने अधिवक्ता श्री रुस्तम के साथ।

मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट पुलिस अधिकारी, पुलिस थाना कोटगेट, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत की गई। परिवादी और उसके अधिवक्ता को सुना गया। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पुलिस द्वारा जांच करने पर अनावेदकों द्वारा परिवादी के साथ धोखाधड़ी किए जाने का तथ्य प्रकाश में आया है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत को पुलिस अधिकारी, पुलिस थाना कोटगेट, बीकानेर को धारा *175(3)* बीएनएसएस के अंतर्गत भेजा जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए तथा जांच कर परिणाम यथाशीघ्र न्यायालय को सूचित किया जाए। फाइल को सूचीबद्ध किया जाए। *21.10.24* इसके परिणाम की प्रतीक्षा में।

एसडी/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट"

उपर्युक्त आदेश पारित करने के बाद, बीएनएसएस की धारा 175 के तहत दायर शिकायत को एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के एसएचओ को डाक से भेजा गया। एसएचओ ने बदले में शिकायत को ही शब्दशः एफआईआर में बदल दिया।

9. अब एफआईआर के गुण-दोष पर विचार करते हुए, इससे पहले कि मैं इसके कारणों को दर्ज करके विस्तार से अपनी राय प्रस्तुत करूं, मैं यह व्यक्त कर सकता हूं कि मैं विद्वान पीपी द्वारा अपनाए गए रुख से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। ऊपर उद्धृत एफआईआर की सामग्री का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी, विद्वान मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

10. सीजेएम के आदेश के अनुसार, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका दृष्टिकोण धारा 175 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करता है। हालांकि, आदेश में उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के किसी भी विश्लेषण या चर्चा पर विस्तार से नहीं बताया गया है। न ही उनके आदेश में इस बात पर कोई संतुष्टि दर्ज की गई है कि पुलिस रिपोर्ट की जांच न्यायिक कठोरता का सामना कैसे करती है।

10.1. विद्वान सीजेएम ने पुलिस को केवल जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, बिना स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित किए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। केवल पुलिस के निष्कर्षों को स्वीकार करना और पारिवारिक विवाद को आपराधिक बनाना पूरी तरह से न्यायिक अनदेखी है।

10.2. आदेश में यह नहीं दर्शाया गया है कि सीजेएम ने शिकायतकर्ता/मां द्वारा अपनी बेटी, पोती और दामाद के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार कथित धोखाधड़ी की गंभीरता का आकलन करने के लिए न्यायिक दिमाग लगाया था या नहीं। इस प्रकार यह रबर-स्टैंप निर्णय लेने के अलावा और कुछ नहीं है। धारा 175(3) बीएनएसएस को बिना किसी तर्क के लागू किया गया है। एफआईआर दर्ज करने का निर्णय पुलिस के प्रारंभिक निष्कर्षों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सहायक दस्तावेज़ मांगकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता/न्याय की किसी भी चूक और न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता था, बजाय इसके कि पुलिस के बयान को सिरे से स्वीकार कर लिया जाए।

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

11. उपर्युक्त संदर्भ में, आइए बीएनएसएस की धारा 175 को देखें ताकि इसके वास्तविक उद्देश्य और अभिप्राय को समझा जा सके। नीचे उसी को पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"संज्ञेय मामले की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

175. *(1)* किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, ऐसे थाने की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र के आदेश के बिना, अध्याय *XIV* के प्रावधानों के तहत जांच या मुकदमा चलाने की शक्ति रखता है*:*

बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक को मामले की जांच करने के लिए कह सकता है।

(2) किसी भी ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी की कार्यवाही किसी भी स्तर पर इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने के लिए ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन सशक्त नहीं था।

(3) धारा *210* के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा *173* की उपधारा *(4)* के अधीन दिए गए शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात तथा पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में आवश्यक जांच करने और प्रस्तुत किए गए निवेदन के पश्चात उपर्युक्त जांच का आदेश दे सकता है।

(4) धारा *210* के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायत प्राप्त होने पर जांच का आदेश दे सकता है, बशर्ते कि-

(क) अपने से वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो*;* और

(ख) लोक सेवक द्वारा उस स्थिति के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करने के बाद जिसके कारण कथित घटना घटी।"

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

12. धारा 156 के अनुरूप, उक्त धारा, संज्ञेय मामलों की जांच में मजिस्ट्रेटों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। यह प्रावधान पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को बिना पूर्व प्राधिकरण के संज्ञेय अपराधों की जांच शुरू करने का अधिकार देता है। इसका आशय यह है कि कथित अपराध ऐसी प्रकृति का है जिसके लिए बिना वारंट के आरोपी की गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है (जैसे हत्या, चोरी या बलात्कार)। इस प्रकार, आमतौर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां अपराध की प्रकृति और गंभीरता की मांग है कि ऐसे संवेदनशील या जटिल मामलों पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उचित ध्यान दिया जाए, ऐसा न करने पर, क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। इसमें निहित अंतर्निहित जांच और संतुलन यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि समाज के खिलाफ कोई भी अपराध दण्डित होने से न छूटे।

12.1. साथ ही, उक्त धारा के तहत शक्ति का दुरुपयोग तुच्छ शिकायतों में जांच करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट न्यायोचित निर्णय पर पहुँचने से पहले अपनी स्वयं की जाँच भी कर सकता है। इस प्रकार प्रावधानों का उद्देश्य न्यायिक सतर्कता की आवश्यकता को संतुलित करते हुए संज्ञेय अपराधों की प्रभावी और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना है।

13. इस चरण में **प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**[2] में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

प्रियंका श्रीवास्तव के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उदाहरणों की श्रृंखला का संदर्भ दिया गया है, उन पर भरोसा किया गया है और उन पर चर्चा की गई है। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए यंत्रवत् निर्देश देने के विरुद्ध बार-बार चेतावनी दी गई है। फिर भी, वर्तमान मामले में उक्त कथन की पूरी तरह से अवहेलना की गई है।

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

[2] **(2015) 6** एससीसी **2874**

13.1. **प्रियंका श्रीवास्तव** (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 156(3) सीआरपीसी, (बीएनएसएस, 2023 की धारा 175(3) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप) पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार माना:

> "*29.* इस स्तर पर यह कहना उचित है कि धारा *156(3)* के तहत शक्ति न्यायिक दिमाग के आवेदन को वारंट करती है। एक कानून की अदालत शामिल है। यह पुलिस नहीं है जो कोड की धारा *154* के चरण में कदम उठाती है। एक वादी अपनी मर्जी से मजिस्ट्रेट के अधिकार का आह्वान नहीं कर सकता। एक सिद्धांतवादी और वास्तव में दुखी नागरिक जिसके हाथ साफ हों, उसे उक्त शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्र पहुंच होनी चाहिए। यह नागरिकों की रक्षा करता है, लेकिन जब विकृत मुकदमे अपने साथी नागरिकों को परेशान करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें रोकने और रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए।
>
> *30.* हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है, जहाँ धारा *156(3)* सीआरपीसी के तहत आवेदनों को आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है। इसके अलावा, एक उचित मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सत्य की पुष्टि करने की सलाह दी जाएगी और वह आरोपों की सत्यता को भी सत्यापित कर सकता है। यह हलफनामा आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन बिना किसी जिम्मेदारी के नियमित तरीके से केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह तब और अधिक परेशान करने वाला और भयावह हो जाता है जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन किसी आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए

2

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

ऐसा नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई व्यक्ति हिसाब चुकता करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

14. वर्तमान मामले पर लौटते हुए, उपरोक्त के आलोक में, सीजेएम द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए जारी निर्देश न्यायिक दिमाग के उचित उपयोग के दोष से ग्रस्त प्रतीत होता है। ऊपर प्रस्तुत एफआईआर से पता चलता है कि शिकायतकर्ता का खुद का दावा, अन्य बातों के साथ, यह है कि

"मेरे दामाद गोरधन लाल सोनी ने धोखे व धोखाधड़ी से मुझसे *8,50,000* रुपए, आठ लाख पैंतालीस हजार रुपए व *100* ग्राम सोना, *2* किलो *700* ग्राम चांदी, सोने व चांदी के आभूषण हड़प लिए हैं। जब मैंने उधार दिए गए रुपए व सोने-चांदी के आभूषण मांगे तो उसने देने से मना कर दिया और गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस षडयंत्र में मेरी बेटी शोभा भी अपने पति के साथ शामिल है। मेरा पोता जो गोरधन जी सोनी का बेटा है, वह भी इस षडयंत्र में बराबर का भागीदार है।"

15. यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त आरोपों को सत्य मान भी लिया जाए, तो भी यह याचिकाकर्ता संख्या 1 (दामाद) द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 (पुत्री) और याचिकाकर्ता संख्या 3 (पोती) के साथ मिलकर शिकायतकर्ता/सास या मां या दादी द्वारा कथित रूप से उधार दिए गए धन और सोने-चांदी के आभूषण लौटाने से इनकार करने का मामला दर्शाता है। मेरे विचार से, शिकायतकर्ता द्वारा कथित रूप से उधार दिए गए धन और सोने-चांदी के आभूषण लौटाने से इनकार करना, याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आपराधिक आरोप नहीं हैं।

15.1. दूसरी ओर, आरोप केवल यह दर्शाते हैं कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ताओं के बीच विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, जिसे एफआईआर का आधार बनाने वाली शिकायत में आपराधिकता का रंग दिया गया है। फिर भी, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध के तत्वों को दर्शाने वाले

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

किसी भी तथ्य का उल्लेख किए बिना, यह पाया कि शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई थी और इस आधार पर पुलिस को बीएनएसएस की धारा 175 (3) के तहत मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। जाहिर है, मेरी राय में, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाला आदेश एक सरसरी और यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था, जो शिकायत की समग्र सामग्री, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए न्यायिक दिमाग के आवेदन की कुल कमी को दर्शाता है।

16. मैं इस प्रकार मानता हूं कि वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

<u>राहत</u>

17. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए उपरोक्त अन्य तर्कों पर विचार किए बिना, याचिका को अनुमति दी जाती है और आईपीसी की धारा 420/406/120 बी के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत संदिग्ध एफआईआर संख्या 266 दिनांक 27.09.2024, पीएस कोटगेट, बीकानेर और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

<u>निष्कर्ष</u>

18. विदा लेने से पहले, पिछले भाग में उल्लिखित कानून की स्थिति के आलोक में, यह देखना और इस बात पर जोर देना समझदारी होगी कि पारिवारिक विवादों के मामलों में, जहां एक रिश्तेदार दूसरे पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय आपराधिक आचरण का आरोप लगाता है, यह सलाह दी जाती है कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले कानून प्रवर्तन और मजिस्ट्रेट दोनों द्वारा अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामलों में, पारिवारिक संबंधों को सुधारने के

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

प्रयासों को प्राथमिकता देते हुए सावधानी से काम करना अनिवार्य है, न कि कलह को बढ़ाना।

18.1. अहिंसक प्रकृति के आरोपों और मजिस्ट्रेटी परीक्षणों से जुड़े विवादों में, खासकर जब करीबी/रक्त संबंधी रिश्तेदार शामिल हों, मजिस्ट्रेटों को ध्यान रखना चाहिए कि शपथ पत्र की प्रथागत आवश्यकता को अक्सर सामान्य टेम्पलेट्स पर निर्भर करते हुए एक औपचारिकता के रूप में माना जाता है। जैसा कि वर्तमान मामले में प्रदर्शित किया गया है, जहां अभिसाक्षी केवल शिकायत की विषय-वस्तु के बारे में जानकारी की पुष्टि करता है, मजिस्ट्रेट को यथासंभव आरोपों की प्रामाणिकता की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी चाहिए। यह मौखिक पूछताछ या अन्य तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकायतकर्ता शिकायत में किए गए दावों को समझता है और उन्हें प्रमाणित करता है, इस प्रकार झूठे या तुच्छ आरोपों को रोकता है।

18.2. मजिस्ट्रेटों को आरोपों की सत्यता और विश्वसनीयता का भी सावधानीपूर्वक पता लगाना चाहिए, कार्रवाई करने से पहले उन्हें सहायक सामग्री के साथ पुष्टि करनी चाहिए। पारिवारिक विवादों में आपराधिक शिकायतों को लापरवाही से या उचित जांच के बिना नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुचित उत्पीड़न हो सकता है। आपराधिक अदालतों को व्यक्तिगत प्रतिशोध या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में काम नहीं करना चाहिए। धारा 175 बीएनएसएस के तहत पारित आदेशों में न्यायिक दिमाग का पूरा उपयोग होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को तुरंत खारिज कर दिया जाए।

19. संक्षेप में, मजिस्ट्रेटों द्वारा सुनवाई योग्य पारिवारिक विवादों में, विशेष रूप से करीबी रिश्तेदारों से जुड़े विवादों में, मजिस्ट्रेटों को पारिवारिक बंधनों को संरक्षित और मजबूत करने के लिए अनुकूल वातावरण का पोषण करने का प्रयास करना चाहिए। शत्रुता को बनाए रखने के बजाय सद्भाव और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने से न केवल संबंधित पक्षों को लाभ होता है, बल्कि भावी पीढ़ियों को भी लंबे समय तक चलने वाले शत्रुता के प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सकता है। पारिवारिक एकता और सौहार्द के स्थायी लाभों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)

जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगली पीढ़ी को शत्रुता के बजाय सद्भाव का माहौल विरासत में मिले।

20. याचिका का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

मोहन/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(27/05/2025 को 03:00:00 PM पर डाउनलोड किया गया)